नव दुनियाँ, भोपाल

7 OCT 2011

बिटिया का संरक्षण

ईरान के राष्ट्रपति भवन के एक कक्ष में बड़ी-सी पट्टी लगी है- 'अल्लाह का सबसे खूबसूरत उपहार है बेटी।' ब्रिटेन में वर्षों से 'महारानी' के राज पर गौरव किया जाता रहा है। भारत के हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में 'देवी' की पूजा-अर्चना होती रही है। फिर भी पिछले दशकों में प्रगति के साथ 'बेटी' को बोझ मान भ्रूण-हत्या, अत्याचार, दहेज की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। कुछ राज्यों में तो लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम होने से विवाह के लिए गाँव-कस्बे में लड़कियाँ मिलनी मुश्किल हो गईं। ऐसे माहौल में मध्यप्रदेश सरकार ने दुर्गा पूजा उत्सव के अंतिम दिन 'बिटिया बचाओ अभियान' का ढोल बजाकर सचमुच सार्थक पहल की है। सरकार ने भ्रूण-हत्या और दहेज हठ के अपराध रोकने के लिए बने वर्तमान कानूनों को सख्ती से लागू करने का संकल्प भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का यह व्यावहारिक प्रयास है कि परिवार के लिए बिटिया को बोझ न मानने के लिए अशक्त गरीब माता-पिता को पेंशन दी जाए और जरूरत पड़ने पर विवाह के बाद भी बेटी के साथ रहने का कानूनी अधिकार मिले। प्रतीक रूप में ही सही, प्रदेश में पाँच लाख बेटियों के पैर पूजने का कार्यक्रम सामाजिक जागरूकता के लिए अभिनव प्रयास है।

उम्मीद की जानी चाहिए कि अन्य राज्य सरकारें भी मध्यप्रदेश का अनुकरण करेंगी

असल में बेटियों को उचित सम्मान, अधिकार और विश्वास दिलाने का काम किसी सरकार पर निर्भर नहीं रह सकता है। यह मुद्दा किसी विशेष क्षेत्र, जाति, समुदाय, धर्म से जुड़ा नहीं है। इसके लिए हर राज्य में सामाजिक जागरूकता लाने की जरूरत है। वर्ष में एक या दो बार पूजा-आराधना या 'डॉटर्स डे' मनाने की औपचारिकताओं की अपेक्षा निरंतर इस मुद्दे पर लोगों की सोच को सकारात्मक बनाना होगा। अब भी कई गैर सरकारी संगठन कुछ राज्यों में काम कर रहे हैं। यूनिसेफ जैसा अंतरराष्ट्रीय संगठन भी दुनियाभर में विभिन्न तरीकों से जागरूकता लाने की कोशिश करता है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि शिक्षित और संपन्न वर्ग में बेटियों के प्रति कटुता का भाव बढ़ा है। जन्म से पूर्व ही कन्या-भ्रूण हत्या की घटनाएँ इस वर्ग में अधिक देखने को मिली हैं। अफ्रीका और खाड़ी के देशों में ही नहीं, योरप में भी लड़कियों के प्रति भेदभाव की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए बेटी बचाओ अभियान अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए प्रेरक कहा जा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अन्य राज्य सरकारें भी मध्यप्रदेश का अनुकरण कर समाज को अधिक सुखी और सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएँगी।